eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

भारतीय विदेशी व्यापार नीति परिवर्तन के विभिन्न चरण–एक परिचय

डा0 मो0 इसरार खानं[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, मिश्रिख, सीतापुर, उ0प्र0

Received: 20 June 2026 Accepted & Reviewed: 28 June 2026, Published: 30 June 2026

Abstract

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति विश्व से मित्रवत एवं भाईचारे की तथा सहयोग पर आधारित रही है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परस्पर न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने में अग्रणी देशों में रहा है। भारतीय विदेश नीति के दृष्टिगत, दक्षिण एशियाई देश एक महत्वपूर्ण भू–भाग है। इस क्षेत्र पर अमेरिका, यूरोप, चीन तथा रुस की दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र के देश–विकासशील गैर– विकसित की श्रेणी में आने के बाद भी उपभोक्ता बाजार की दृष्टि से विशाल जनसंख्या वाले देश हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया विश्व के कुल क्षेत्रफल का करीब 3.5% है, जबकि लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन देशों की सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक जैसे हैं, किंतु इन देशों में आपसी समन्वय एवं विश्वास का अभाव है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का आपसी व्यापार संपूर्ण विश्व व्यापार का लगभग 5% है ,जबकि अन्य महाद्वीपों एवं राष्ट्रों से शेष 95% व्यापारिक संबंध रखते हैं। यही कारण है कि इन देशों का पड़ोसी देशों से वैश्विक व्यापार का मात्र 1% ही निवेश है।

मुख्य शब्द– राष्ट्रवाद, भारतीय विदेशी व्यापार नीति, परिवर्तन, चरण, विश्व, दक्षिण एशिया

Introduction

भारतीय विदेशी व्यापार नीति ने 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात से ही एक लंबा सफर तय किया है। यह सफर आदर्शवाद से शुरू होकर व्यावहारिक ,कूटनीतिक और वर्तमान में एक शक्तिशाली वैश्विक नेतृत्व तक पहुंची है। आर्थिक कूटनीति और उदारीकरण (1991–1998)– 1991 मे भारत ने एक नई राह चुनी और लुक ईस्ट (Look East) नीति अपनाई, और अर्थव्यवस्था को वैश्विक राष्ट्रो के लिए खोल दिय।

भारतीय विदेश व्यापार नीति की निरंतरता के विभिन्न चरण–

(1) प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की विदेशी व्यापार नीति– जवाहरलाल नेहरू ने करीब 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रुप मे भारत का नेतृत्व किया। नेहरू की विदेश व्यापार नीति मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित थी, इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना और देश में भारी उद्योगों का निर्माण तथा छोटे व्यापार को बढ़ावा देना था

विदेशी व्यापार के निम्न बिंदु–

1–आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution)– विदेशों से वस्तुओ के आयात के बजाय उन्हें अपने देश में ही निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए विदेशी विनिमय की कमी के कारण गैर–जरूरी वस्तुओ के आयात पर

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

सख्त प्रतिबंध लगाए गए आज का प्रभावरू– आज भी श्आत्मनिर्भर भारतश अभियान और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति इसी विचार से जुड़ी हैं।

2–राज्य का नियंत्रण और संरक्षण–1956 की औद्योगिक नीति के तहत बुनियादी उद्योगों (जैसे लोहा, स्टील) को सरकारी नियंत्रण में रखा गया ताकि वे बाहरी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रहें।

आज का प्रभाव– आज भी रणनीतिक क्षेत्रों और रक्षा उत्पादन में सरकार की मजबूत पकड़ और संरक्षण की नीति इसी सोच का परिणाम है।

नेहरू काल– शीत युद्ध के दौरान भारत ने पूंजीवादी (अमेरिका) और साम्यवादी (सोवियत संघ) दोनों गुटों से स्वतंत्र रहकर व्यापार और तकनीकी दक्षता प्राप्त की आज की श्मल्टी–अलाइनमेंट नीति कृ जहाँ भारत अमेरिका, रूस और क्वाड (QUAD) जैसे समूहों के साथ संबंध बनाए रखा। यह नीति नेहरू के स्वतंत्र दृष्टिकोण पर ही टिकी है इन्होंने ने बांडुंग सम्मेलन जैसे मंचों के माध्यम से एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंध मजबूत किए।

आज का प्रभाव– आज का श्ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आसियान के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना उसी पुरानी नीति की परम्परा है। पं०नेहरू की विदेश नीति में जहां उस समय कड़े आयात प्रतिबंध थे, वहीं आधुनिक भारत की विदेशी व्यापार नीति, निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात को कम करने पर केंद्रित थी

पंडित नेहरू अपने शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों की वृद्धि की अपेक्षा विश्व राष्ट्रों से मैत्री संबंधों पर जोर दिया । उन्होंने पड़ोसी मुल्कों चीन से इतनी घनिष्ठता व्यक्त की कि हिंदी चीनी भाई–भाई का नारा गुंज ने लगा। भारत के विशाल जनसंख्या के लिए मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था सरकार के लिए एक चुनौती थी 1

प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कालीन विदेशी व्यापार नीति– लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुए जो श्सादा जीवन उच्च विचार श्के मूर्त रूप थे। शास्त्री जी के समय भारत के समक्ष कई राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां थी। शास्त्री जी ने भारत के विदेश नीति को प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पड़ोसी राष्ट्रो से मैत्री संबंधो को आगे बढ़ाया। सन 1965 की भारत–पाक युद्ध में उनके रणनीतिक कौशल का नतिजा था कि भारत ने पाकिस्तान को धुल चटाई। 2.

प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय (1964–1966) की विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य आत्म–निर्भर और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना था। उस समय देश गंभीर खाद्यान्न संकट और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा था। आयात–निर्यात मे असन्तुलन बना हुआ था। और व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था।

विदेशी व्यापार और आर्थिक नीतियां–

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

1. खाद्य आयात पर निर्भरता कम करना– उस समय भारत अनाज के लिए विदेशों (खासकर अमेरिका के च्स–480 कार्यक्रम) पर निर्भर था। शास्त्री जी ने आयात को कम करने के लिए देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और हरित क्रांति की नींव रखी। ताकि देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जाएं

2. निर्यात प्रोत्साहन–

उनकी नीति ष्आयात प्रतिस्थापनष् से ष्निर्यात संवर्धन की ओर धीरे–धीरे बढ़ने लगी थी। सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार प्रोत्साहन वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया ताकि देश आवश्यक मशीनरी का आयात कर उत्पादन को बढ़ावा दे सके।

3. विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना–

शास्त्री जी की नीतियों ने सरकारी खर्चों पर नियंत्रण किया। जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। इससे भारत की विदेशों से मिलने वाली सशर्त ऋण पर निर्भरता कम हो और देश आत्म निर्भर बन सके।

4. छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा (MSMEs)–

सरकार ने छोटे उद्योगों और कृषि आधारित व्यवसायों को सहायता दी। जिससे न केवल आम लोगों को रोजगार मिला, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली।

5. आयात में कटौती– देश के सामने विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत संकट था। इसलिए, केवल जरूरी चीजों (जैसे रक्षा उपकरण, खाद्यान्न और जरूरी मशीनरी) को छोड़कर बाकी सभी गैर–जरूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

6.विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार– व्यापार और शांतिपूर्ण संबंध को बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने 1964 में श्रीलंका के साथ मानवीय और व्यापारिक समझौता किया। 2

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कालीन विदेश व्यापार नीति–श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी स उस समय देश अनेक समस्याओं एव चुनौतियों से जूझ रहा था। जिसका उन्होंने बड़े कौशल और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए मोकाबला किया।

श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल (1966–1977) में भारत की विदेश व्यापार नीति संरक्षणवादी और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी । इस दौरान विदेशी मुद्रा संचयन और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम और लाइसेंस व्यवस्था लागू की गई।

विदेश और व्यापार नीति–

आयात प्रतिस्थापन– इस नीति का मुख्य उद्देश्य विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करना तथा इसके बजाय भारत में ही वे चीजें तैयार करने पर जोर दिया गया, ताकि देश का धन विदेशो को न जाएं और देश में मुद्रा भंडार बढ़े।

लाइसेंस राज और कोटा– कोई भी नया उद्योग शुरू करने या विदेशों से कच्चा माल मंगाने के लिए सरकार से विशेष अनुमति (लाइसेंस) लेनी पड़ती थी। इसे श्लाइसेंस–परमिट राजश कहा जाता था ।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

विदेशी मुद्रा का कड़ा नियम (FERA 1973)– विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिए उनके समय में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) लागू किया गया। इसके तहत विदेशी कंपनियों और मुद्रा के लेन देन पर कड़ी नजर रखी गयी ।

निर्यात प्रोत्साहन– यह नीति मुख्य रूप से आयात कम करने पर थी, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सरकार ने चुनिंदा पारंपरिक वस्तुओं (जैसे चाय, जूट, और मसाले) के निर्यात को बढ़ावा दिया ।

सोवियत संघ के साथ घनिष्ठता– विदेश नीति में इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, लेकिन व्यापार के मामले में सोवियत संघ के साथ रुपये–रूबल मे व्यापार समझौते किए, जिससे पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो सके।

प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई काल में विदेशी व्यापार नीति– मोरारजी देसाई (1977–1979) के कार्यकाल में भारत की विदेश व्यापार नीति संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। सरकार ने विदेशी निवेश को सीमित किया और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया। इसके तहत विदेशी कंपनियों पर सख्त नियम लगाए, जिससे कोका–कोला और आईबीएम जैसी कंपनियों ने भारत छोड़ दिया।

व्यापारिक और आर्थिक नीतियाँ –

1. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)–

सरकार ने फेरा (FERA) कानून को सख्ती से लागू किया। इसके अनुसार, विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी (इक्विटी) 40ः तक ही रखने की अनुमति दी। 2 आयात पर प्रतिबंध– सरकार ने गैर जरुरी वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सरकार का जोर घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने पर था।

3 . निर्यात को बढ़ावा रू– सरकार ने स्थानीय कुटीर उद्योगों और छोटे व्यवसायों (छोटे कारोबारियों) के निर्यात को प्राथमिकता दी। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुआ।

4. औद्योगिक नीति (1977)– वर्ष 1977 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार, विदेशी कंपनियों को घरेलू उद्योगों के समान श्रेणी में रखा गया। लेकिन शर्त थी कि वे भारतीय कानूनों का पालन करें।

5. गैर–गठबंधन की नीति–

देसाई सरकार ने किसी भी बड़े गुट (अमेरिका या सोवियत संघ) के दबाव में आने से इन्कार कर दिया। उन्होंने सच्चे गैर–गठबंधन को अपनाया और सभी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार संबंधों पर जोर दिया। 4

6 प्रधानमंत्री राजीव गांधी काल में विदेशी व्यापार नीति – प्रधानमंत्री राजीव गांधी (1984–1989) के कार्यकाल में विदेशी व्यापार नीति ने श्आयात–निर्यात उदारीकरण और श्तकनीकी आधुनिकीकरणश की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना शुरू किया, जिससे 1991 के पूर्ण आर्थिक सुधारों की नींव रखीं गयी।

विदेश व्यापार और आर्थिक कूटनीति की प्रमुख विशेषताएं –

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

तकनीकी आयात का उदारीकरण– उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार उपकरणों के आयात को आसान बनाया। इससे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्रांति की शुरुआत हुई।

लाइसेंस राज में ढील– कई उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाया। जिससे विदेशी तकनीक के उपयोग और निवेश आकर्षित करने में मदद मिली।

निर्यात संवर्धन– विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बनाई गईं। इसके लिए गुणवत्ता, नियंत्रण और तकनीकी सहयोग पर बल दिया गया।

विदेशी कूटनीति और व्यापाररू– सोवियत संघ के साथ व्यापारिक संबंध रखते हुए, उन्होंने अमेरिका के साथ उच्च तकनीक (सुपर कंप्यूटर) के लिए व्यापारिक समझौते किए।

सार्क (SAARC) की स्थापना– 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना था।

राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति को नवीन परिवर्तनों के साथ निरंतरता प्रदान की। वे भारत को 21वीं सदी के विज्ञान एवं तकनीकी का महाशक्ति बनाना चाहते थे जिसमें वह सफल भी रहे। 5

7. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल की विदेश व्यापार नीति– प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल (1991–1996) की विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य ष्सहायता नहीं, व्यापारष् के सिद्धांत को अपनाया। राव सरकार ने 1991 के आर्थिक संकट से उबारने के लिए उदारीकरण की शुरुआत की। इसके तहत आयात शुल्क कम किए गए, लाइसेंस राज खत्म किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया गया। जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में व्यापार में छुट मिली

विदेश व्यापार नीति के प्रमुख कारक– इस काल में विश्व पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रबल हुआ और जून 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारत के सहभागिता से अमेरिका, चीन,जापान तथा यूरोपीय, अफ्रीकी, एशिया तथा लैटिन अमेरिकी देशों से हमारे संबंध बेहतर हुए और भारत का तृतीय विश्व के सामाजिक, आर्थिक,व्यापारिक, संस्कृत आदान–प्रदान में रचनात्मक उछाल आया।

आयात–निर्यात उदारीकरण (EXIM Policy)– विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए आयात प्रतिबंधों को काफी हद तक हटा लिया गया।

रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Money)–भारतीय मुद्रा (रुपये) का अवमूल्यन किया गया, जिससे निर्यात सस्ता और विदेशी बाजारों में मुद्रा अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया।

आयात शुल्क में कमी– घरेलू उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें नई तकनीक तक पहुंच बनाने के लिए आयात शुल्क को कम कर दिया गया।

लुक ईस्ट नीति– राव ने दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों (ASEAN) के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए 1992 में इस नीति की शुरुआत की। इन व्यापारिक और आर्थिक सुधारों के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत हुआ और विदेशी व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल की विदेशी व्यापार नीतिरू– प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल (1998–2004) में विदेशी व्यापार नीति (EXIM Policy) का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण, उदारीकरण और

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

निर्यात को बढ़ावा देना था। उनकी सरकार ने व्यापार बाधाओं को कम किया, विदेशी निवेश के लिए नियम आसान किए, और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर बल दिया।

विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं–

निर्यात संवर्धन– सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में छूट की योजनाएं लागू कीं। SEZ की शुरुआत–उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाने की नींव रखी गई।

इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास– माल की आवाजाही को आसान करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बड़ी सड़क परियोजनाएं शुरू की गईं। आसियान(ASEAN)और पड़ोसी देशों से व्यापार– सरकार ने श्लुक ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए। इसके अलावा सार्क (SAARC) देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया गया।

निजीकरण को बढ़ावा– विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया। इन नीतियों का परिणाम यह हुआ कि भारत का विदेशी मुद्रा कोष मजबूत हुआ और तकनीकी क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह कालीन विदेशी व्यापार नीतिरू– आरबीआई गवर्नर, प्रोफेसर तथा अर्थशास्त्री डा० मनमोहन सिंह (2004–2014) के कार्य काल में भारत की विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना और निर्यात को विकास और रोजगार वृद्धि का साधन बनाना था।

विदेश व्यापार नीतियों की मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां–

1. पांच–वर्षीय एकीकृत नीति– डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने पारंपरिक शनिर्यात–आयात (EXIM) नीतियों के वार्षिक बदलाव को समाप्त कर दिया। इसके बजाय, 2004–2009 और 2009–2014 के लिए दीर्घकालिक और व्यापक शविदेश व्यापार नीतियां पेश की, जिसका उद्देश्य व्यापार लागत कम करना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था।

2. वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी–लक्ष्य– इस नीति का लक्ष्य 5 वर्षों में वैश्विक व्यापारिक माल, व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दोगुना करना था। इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया गया और कृषि तथा उद्योग ने निर्यात में शानदार वृद्धि की।

3. मुक्त व्यापार समझौते– अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एकीकृत करने के लिए कई बड़े आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 2009 में आसियान के साथ वस्तुओं के व्यापार का समझौता, 2009 में दक्षिण कोरिया के साथ और 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों को अंतिम रूप दिया गया।

4. रोजगार और अवसंरचना पर जोर– केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बजाय, इस नीति ने विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) और ैप्क्म (राज्यों के लिए निर्यात अवसंरचना विकास) जैसी योजनाएं शुरू की गईं।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

5. तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन– निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए Status Holders जैसी मान्यताएं दी गईं। तकनीकी उन्नयन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क–मुक्त आयात की अनुमति दी गई और Duty Credit Scrips जैसे प्रोत्साहन दिए गए।

भारत–पाक के मध्य आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों में प्रगति हुई। डा० सिंह ने भारत की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति में बदलाव के लिए कई कदम उठाए। इससे भारत विकास की ओर अग्रसर हुआ और विश्व समुदाय में इसकी सशक्त उपस्थिति को स्वीकृति मिली। 6

9 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल की विदेशी व्यापार नीति– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश व्यापार नीति का मुख्य लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को +2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। यह नीति करों में छूट, व्यापार को आसान बनाने और ई–कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इस नीति के प्रमुख बिंदु–

लॉन्ग–टर्म लक्ष्य– इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाना है। 2 ट्रिलियन निर्यात– 2030 तक कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं) को 2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ई–कॉमर्स निर्यात–ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाले छोटे व्यापारियों (डैडमे) के लिए विशेष योजनाएं हैं। इससे छोटे शहरों के कारीगर भी विदेशों में अपना माल आसानी से बेच सकेंगे।

सूट/छूट की सुविधा– निर्यातकों के लिए करों में छूट और निर्यात संवर्धन योजनाओं को जारी रखा गया है।

मुद्रा में व्यापार– अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि व्यापार में आसानी हो और रुपए में व्यापार को प्रोत्साहन मिले ।

भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों तथा दक्षिण एशियाई देशों के संकट में हमेशा साथ खड़ा रहा है जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनानें में सहायक सिद्ध हुआ है। पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को शुदृढ़ किया जा सका है।

निष्कर्ष (Conclusion)–भारत की विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर करना और वैश्विक बाजार में भारत को एक मजबूत शक्ति बनाना है।

वर्तमान विदेश व्यापार नीति (FTP 2023)–

लक्ष्य– इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन (वस्तु और सेवाओं को मिलाकर) तक पहुँचाना है।

स्थानीय स्तर पर ध्यान– डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हबश (जिलों को निर्यात केंद्र बनाना) के जरिए स्थानीय उत्पादों को सीधे विदेशों में भेजा जा रहा है। पेपरलेस और डिजिटल प्रक्रिया– निर्यातकों को दी जाने वाली मंजूरी को तेज और आसान बना दिया गया है।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 06, June 2026

भारतीय रुपये को बढ़ावा– अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम हो।

चुनौतियां– इन नीतियो का उद्देश्य दुरगामी, लेकिन सफल बनाने के लिए विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे , कागजी कार्रवाई में कमी, और वैश्विक आर्थिक संकटों से बचाव की आवश्यकता है।

भविष्य की दिशा– भविष्य में इस नीति की सफलता घरेलू उत्पादन की गुणवत्ता, बेहतर लॉजिस्टिक्स (परिवहन लागत में कमी) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों (FTAs) के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति में पड़ोसी देशों और दक्षिण एशियाई देशों के प्रत्येक संकट में उनके साथ खड़ा रहा है। जिससे क्षेत्र मे शांति और समृद्धि हो। इसी स्थिरता,विश्वास और प्रगति की आकांक्षा से भारत ने हमेशा कार्य किया है।

भारत की स्थिर विदेश नीति– प्रथमत, भारत अपने निर्धारित लक्ष्यो को आगे बढ़ाने और दक्षिण एशियाई देशों के विकास में सहयोग एवं प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। द्वितीय ,पड़ोसी देशों को आवश्यक सहायता देकर भारत क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को कायम करने में सफलता अर्जित कर सकेगा। इससे चीनी गतिविधियों एवं कूट चालो पर लगाम लगाना संभव हो सकेगा । इसीलिए भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों से जुड़ाव एवं सहयोग की नीति पर चलता रहा है। तृतीय, निरंतर सौहार्द और स्थिरता के सापेक्ष लोगों के मध्य संबंधों और गहरी संस्कृतिक सामानता को स्थापित किया जा सकेगा । अन्ततः क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भारतीय प्रतिबद्धता को चरितार्थ किया जा सकेगा। 7

सन्दर्भ सूची–

(1) अटल बिहारी वाजपेई भारत की विदेश नीति, राजपाल एंड सन्स ,नई दिल्ली 1979, पृष्ठ सं०– 26–27.

(2) डा० आर०पी० जोशी, डा० अमिता अग्रवालरू अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, शील सन्स प्रकाशन,जयपुर 1999, पृ सं०–280.

(3) विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) का विस्तृत विवरण Angel One https://www-angelone-in –

(4) विदेशी व्यापार नीति Ministry of Food Processing Industries https://www-mofpi-gov-in-

(5) भारत की विदेश व्यापार नीति eGyankosh] https://egyankosh-ac.

(6) भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 नए विचार और पुरानी चुनौतियां NUS Institute of South Asian Studies] https://www-isas-nusedu-sg

(7) डॉ०बी०सिंह गहलोत भारतीय विदेश नीति, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2016 ,पृ० सं०– 71.